एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से उम्मीदें

10 देशों से मिले 20,559 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर के आकार वाली अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए लिए योगी सरकार अगले दो वर्षों के अंदर प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से उम्मीदें संजोये है। सरकार ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से सरकार का 10 लाख करोड़ रुपये निवेश जुटाने का इरादा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिये निवेश आकर्षित करने के लिए अगले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किये जाएंगे। निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए शिलान्यास समारोहों (ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह) के आयोजन का सिलसिला भी जारी रहेगा।

पिछले पांच वर्षों में प्रदेश को निवेश का गंतव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने नियमों का सरलीकरण

तीसरे शिलान्यास समारोह में 70 हजार करोड़ की निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी

करने के साथ करीब दो दर्जन नीतियों को अमली जामा पहनाया है। इस वजह से राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भी उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है। उद्योग विभाग को सिंगापुर, यूएस, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया समेत 10 देशों से 20,559 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। विभाग की ओर से 36 हजार से अधिक संभावित रोजगार वाली 39 परियोजनाओं के लिए भूमि भी आवंटित कर दी गई है।

योगी सरकार के पहले कार्यकाल में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में 4.28 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। पहले कार्यकाल में आयोजित दो शिलान्यास समारोहों (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) के माध्यम से करीब तीन लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार अब तीसरा शिलान्यास समारोह तीन जून को आयोजित करने की तैयारी में जुटी है। तीसरे शिलान्यास समारोह के जरिये 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है।

पूर्व में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों में से 1.70 लाख करोड़ रुपये की 802 परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जबकि 57,186 करोड़ रुपये की 232 परियोजनाओं में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। इसमें 1.4 लाख लोगों को रोजगार भी मिले हैं। वहीं 47,484 करोड़ रुपये की 149 परियोजनाओं और 65,029 करोड़ रुपये की 421 परियोजनाओं में जल्द उत्पादन शुरू होने वाला है। इससे 12.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।